ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in June 2025

हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की क्षेत्रीय विषमताएँ: शिक्षा, रोजगार और जनसांख्यिकीय संकेतकों का विश्लेषण

पंकज (शोधकर्ता), भूगोल विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)
डॉ. ओमप्रकाश शर्मा (सहायक प्राध्यापक), भूगोल विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

सार

हरियाणा में उच्च प्रति व्यक्ति आय और तेजी से शहरीकरण के बावजूद लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं। यह अध्ययन राज्य के सभी 22 जिलों में महिला सशक्तिकरण की क्षेत्रीय असमानताओं का विश्लेषण शिक्षा, रोजगार और जनसांख्यिकीय संकेतकों—लिंगानुपात, विवाह की आयु और प्रजनन स्वास्थ्य—के आधार पर करता है। अध्ययन में जनगढ़ना 2011, एनएफएचएस -4, एनएफएचएस -5, पीएलएफएस और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते हुए जिलों को पाँच क्षेत्रीय समूहों में वर्गीकृत किया गया। विश्लेषण में पंचकूला, गुरुग्राम, रोहतक और अंबाला की स्थिति कई संकेतकों पर अपेक्षाकृत बेहतर, जबकि नूंह, पलवल, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी की स्थिति कमजोर पाई गई। सहसंबंध विश्लेषण से महिला साक्षरता का महिला श्रम-बल भागीदारी और घरेलू निर्णय-निर्माण से मजबूत संबंध सामने आया, जबकि लिंगानुपात की समस्या केवल शिक्षा से हल होती नहीं दिखी। अध्ययन निष्कर्ष देता है कि क्षेत्रीय लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए जिला-विशिष्ट नीतियों, बेहतर शिक्षा, सुरक्षित परिवहन, कौशल-आधारित रोजगार तथा पीसीपीएएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

विशेष शब्द: महिला सशक्तिकरण; हरियाणा; क्षेत्रीय असमानता; महिला साक्षरता; लिंगानुपात; महिला श्रम बल भागीदारी; एनएफएचएस -5

1. परिचय

महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ महिलाओं की अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने की क्षमता, अवसर और अधिकार में वृद्धि से है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण को केवल महिलाओं के कल्याण तक सीमित न मानकर सामाजिक एवं मानव विकास के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जाता है। सतत विकास लक्ष्य–5, अर्थात् लैंगिक समानता, के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति के नियमित मूल्यांकन को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इस संदर्भ में हरियाणा का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है। हरियाणा भारत के आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में शामिल है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक है, कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है तथा गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हुआ है। सामान्यतः आर्थिक विकास के इस स्तर के साथ महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी समान रूप से सुधार की अपेक्षा की जाती है, लेकिन हरियाणा की वास्तविक स्थिति इस संबंध को अधिक जटिल बनाती है।

हरियाणा में आर्थिक प्रगति के बावजूद अनेक लैंगिक असमानताएँ लंबे समय से दिखाई देती रही हैं। राज्य का लिंगानुपात ऐतिहासिक रूप से चिंता का विषय रहा है तथा पुत्र-प्राथमिकता और लिंग आधारित भेदभाव जैसी सामाजिक प्रवृत्तियों ने महिलाओं और बालिकाओं की जनसांख्यिकीय स्थिति को प्रभावित किया है। इसी प्रकार, महिलाओं की श्रम-शक्ति भागीदारी राज्य के आर्थिक विकास के अनुपात में अपेक्षाकृत सीमित रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के बावजूद माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर भी महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस प्रकार, आर्थिक विकास अपने आप महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने की क्षमता और जनसांख्यिकीय स्थिति में समान सुधार सुनिश्चित नहीं करता। हरियाणा की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी आंतरिक क्षेत्रीय विविधता है। राज्य के सभी जिलों में महिलाओं की स्थिति समान नहीं है। एन सी आर से जुड़े तथा उत्तरी क्षेत्रों के कुछ जिलों में महिला शिक्षा, रोजगार के अवसर और अन्य सामाजिक संकेतकों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई देती है, जबकि दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों के कई जिलों में महिलाओं से संबंधित विभिन्न संकेतकों पर अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति देखने को मिलती है। सामाजिक संरचना, शहरीकरण, शिक्षा की उपलब्धता, रोजगार के अवसर, परिवहन सुविधाएँ, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति और पारंपरिक लैंगिक मान्यताएँ इन क्षेत्रीय अंतरों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए केवल हरियाणा के राज्य-स्तरीय औसत आंकड़ों के आधार पर महिलाओं की वास्तविक स्थिति को समझना पर्याप्त नहीं है। राज्य-स्तरीय आंकड़े जिलों के बीच मौजूद महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय असमानताओं को छिपा सकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जिला स्तर पर शिक्षा, रोजगार और जनसांख्यिकीय संकेतकों का तुलनात्मक एवं क्षेत्रीय विश्लेषण आवश्यक है।

इसी आधार पर प्रस्तुत शोध-पत्र में हरियाणा के जिलों में महिला सशक्तिकरण की क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन किया गया है। इसमें विशेष रूप से महिला शिक्षा, रोजगार एवं श्रम-शक्ति भागीदारी तथा लिंगानुपात जैसे जनसांख्यिकीय संकेतकों को आधार

बनाया गया है। विभिन्न जिलों और क्षेत्रीय समूहों की तुलना के साथ-साथ इन संकेतकों के बीच सांख्यिकीय संबंधों का भी विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि हरियाणा में आर्थिक विकास के बावजूद महिला सशक्तिकरण में क्षेत्रीय अंतर क्यों बने हुए हैं तथा किन क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अधिक केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है।

2. संबंधित साहित्य की समीक्षा

हरियाणा में जेंडर और विकास पर मौजूद रिसर्च को तीन मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) पर आधारित है। इसने राज्य के खराब सेक्स रेश्यो और इसके सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों का विस्तार से अध्ययन किया है। इसमें इसे पितृसत्तात्मक विरासत के नियमों, दहेज प्रथा और ज़मीन के मालिक खेतिहर समाज में बेटियों की आर्थिक अहमियत कम होने से जोड़ा गया है। जनगणना और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डेटा का इस्तेमाल करने वाली स्टडीज़ ने बार-बार हरियाणा और पंजाब को भारत के डेमोग्राफिक बदलाव में एक अलग मामले के तौर पर दिखाया है। यह एक ऐसा राज्य है जहां आय बढ़ने और फर्टिलिटी (प्रजनन दर) घटने के बावजूद जन्म के समय सेक्स रेश्यो में उसी अनुपात में सुधार नहीं हुआ है। दूसरा हिस्सा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के दौरों का इस्तेमाल करके महिलाओं के सशक्तिकरण के पैमानों, जैसे फैसले लेने की आज़ादी, संपत्ति का मालिकाना हक और आने-जाने की आज़ादी को ट्रैक करता है। इस रिसर्च से पता चलता है कि हालांकि एनएफएचएस -4 (2015-16) और एनएफएचएस -5 (2019-21) के बीच हरियाणा ने बैंक अकाउंट रखने और घर के फैसलों में भागीदारी जैसे पैमानों पर सुधार दिखाया है, लेकिन यह रोज़गार और आर्थिक आज़ादी से जुड़े पैमानों पर अभी भी पीछे है। साथ ही, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान (जिसे राज्य के पानीपत से ही शुरू किया गया था) से पहले हुई बढ़त के बावजूद, 2022 के बाद कुछ ज़िलों में जन्म के समय सेक्स रेश्यो में फिर से गिरावट देखी गई है।

तीसरा हिस्सा लेबर इकोनॉमिक्स (श्रम अर्थशास्त्र) से जुड़ा है। इसने तेज़ी से विकास करने वाले खेतिहर राज्यों में महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी घटने की पहेली की जांच की है। वर्ल्ड बैंक और NSSO/PLFS पर आधारित कई एनालिसिस से पता चला है कि 2000 के दशक के मध्य के बाद हरियाणा में महिलाओं की काम में भागीदारी की दर तेज़ी से गिरी, जबकि पुरुषों की भागीदारी और घर की आय बढ़ी। इस पैटर्न के पीछे आय का असर, खेती में मशीनीकरण (जिससे महिला मज़दूरों की जगह मशीनों ने ले ली), महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर रोक लगाने वाले सामाजिक नियम और ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित, सैलरी वाली गैर-खेतीहर नौकरी की कमी जैसे कारण बताए गए हैं। कुल मिलाकर, यह रिसर्च हरियाणा की जेंडर से जुड़ी पहेली के अलग-अलग हिस्सों को तो सामने लाती है, लेकिन शायद ही कभी उन्हें राज्य के अंदर के ज़िलों के स्तर पर एक ही तुलनात्मक ढांचे में जोड़ती है—और यह पेपर इसी कमी को दूर करने की कोशिश करता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. हरियाणा में महिला साक्षरता, स्कूल छोड़ने की दर तथा उच्च शिक्षा तक पहुँच में जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर विद्यमान भिन्नताओं का अध्ययन एवं तुलनात्मक विश्लेषण करना।
2. हरियाणा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा विभिन्न जिलों में महिला श्रम-शक्ति भागीदारी और क्षेत्रवार रोजगार प्रतिरूपों में विद्यमान असमानताओं का अध्ययन करना।
3. महिलाओं की स्थिति से संबंधित प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतकों—लिंगानुपात, जन्म के समय लिंगानुपात, विवाह की आयु तथा प्रजनन स्वास्थ्य—के क्षेत्रीय प्रतिरूपों का विश्लेषण करना।

4. शोध पद्धति

शोध अभिकल्प: अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प अपनाया गया। जिला-स्तरीय तुलना के लिए अन्वेषणात्मक तथा विभिन्न संकेतकों के संबंधों की जांच के लिए सहसंबंधात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया।

आंकड़ों के स्रोत: आंकड़े भारत की जनगणना 2011, एनएफएचएस -4 (2015–16), एनएफएचएस -5 (2019–21), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण तथा UDISE+ से प्राप्त किए गए। जहाँ पूर्ण जिला-स्तरीय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, वहाँ उपलब्ध आधारभूत आंकड़ों और राज्य-स्तरीय प्रवृत्तियों के आधार पर सांकेतिक अनुमान का उपयोग किया गया।

विश्लेषणात्मक उपकरण: जिला एवं क्षेत्रीय तुलना के लिए औसत, परास और प्रतिशत अंतर तथा संकेतकों के बीच संबंधों के लिए कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया गया। जिलों को एनसीआर -समीपवर्ती, उत्तरी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी हरियाणा के पाँच क्षेत्रीय समूहों में वर्गीकृत किया गया।

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in June 2025

अध्ययन क्षेत्र एवं अवधि: अध्ययन में हरियाणा के सभी 22 जिले शामिल किए गए तथा वर्ष 2011 से 2023 तक उपलब्ध सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

5. आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

जनसांख्यिकीय संकेतक—लिंगानुपात एवं प्रजनन स्वास्थ्य: तालिका 1 में एनएफएचएस -4 और एनएफएचएस -5 के बीच हरियाणा के प्रमुख जनसांख्यिकीय एवं महिला सशक्तिकरण संबंधी संकेतकों में हुए परिवर्तनों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, हरियाणा की स्थिति को व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ में समझने के लिए इन संकेतकों की तुलना एनएफएचएस -5 के अखिल भारतीय आंकड़ों से की गई है। इस तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से लिंगानुपात, जन्म के समय लिंगानुपात, विवाह की आयु, प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलाओं की निर्णय-निर्माण में भागीदारी जैसे संकेतकों में समय के साथ हुए सुधार अथवा असमानताओं को समझने का प्रयास किया गया है। यह विश्लेषण यह पहचानने में भी सहायक है कि महिला सशक्तिकरण के विभिन्न जनसांख्यिकीय आयामों में हरियाणा की स्थिति राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहाँ बेहतर है और किन क्षेत्रों में अभी भी सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

तालिका 1: हरियाणा — महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े चुनिंदा संकेतक, एनएफएचएस -4 बनाम एनएफएचएस -5, भारत के साथ तुलना

इंडिकेटर	एनएफएचएस-4 (2015-16)	एनएफएचएस-5 (2019-21)	भारत NFHS-5
जन्म के समय लिंगानुपात (प्रति 1000 लड़कों पर)	836 (एनएफएचएस-4)	893 (एनएफएचएस-5)	929 (भारत, एनएफएचएस -5)
10 साल से ज़्यादा स्कूलिंग वाली महिलाएँ (15-49 साल की)	31.4%	41.9%	41.0%
साक्षर महिलाएँ	68.6%	74.0%	71.5%
ऑपरेशनल बैंक अकाउंट वाली महिलाएँ	58.5%	81.6%	78.6%
घर के फ़ैसलों में शामिल होने वाली विवाहित महिलाएँ	77.8%	88.5%	88.7%
पिछले 12 महीनों में काम करने वाली और नकद भुगतान पाने वाली महिलाएँ	17.2%	18.9%	25.4%
संस्थागत प्रसव (अस्पताल में जन्म)	80.4%	91.4%	88.6%
कुल प्रजनन दर	2.3	2.0	2.0
बाल विवाह (20-24 साल की महिलाएँ जिनकी शादी 18 साल से पहले हुई)	18.5%	12.0%	23.3%

स्रोत: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-21) की राज्य-वार फ़ैक्ट शीट से संकलित।

तालिका 1 कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। एनएफएचएस-4 से एनएफएचएस -5 के बीच जन्म के समय लिंगानुपात 836 से बढ़कर 893, महिलाओं के बैंक खातों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि तथा घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 88.5% हो गई। हालांकि, नकद भुगतान वाला काम करने वाली महिलाओं का अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम (18.9% बनाम 25.4%) रहा, जो सीमित आर्थिक भागीदारी को दर्शाता है। साथ ही, बाद के सिविल रजिस्ट्रेशन आंकड़ों में जन्म के समय लिंगानुपात में पुनः गिरावट का संकेत मिला। इससे स्पष्ट होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीसीपीएएनडीटी अधिनियम से प्राप्त सुधारों को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

शिक्षा से जुड़े इंडिकेटर

तालिका 2: लिंग और शिक्षा के स्तर के अनुसार सकल नामांकन अनुपात, हरियाणा

शिक्षा का स्तर	लड़कों का GER %	लड़कियों का GER %	जेंडर गैप (pp)
प्राथमिक (I-V)	98.7	97.9	0.8
उच्च प्राथमिक (VI-VIII)	94.2	91.6	2.6
माध्यमिक (IX-X)	86.5	80.3	6.2
उच्चतर माध्यमिक (XI-XII)	68.4	58.7	9.7
उच्च शिक्षा (18-23 वर्ष)	32.8	27.1	5.7

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in June 2025

स्रोत: UDISE+ रिपोर्ट, हरियाणा शिक्षा विभाग और ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) के नवीनतम उपलब्ध राउंड से संकलित।

रोज़गार और आर्थिक भागीदारी

तालिका 3: महिला कामगारों का सेक्टर-वार वितरण, हरियाणा (ग्रामीण बनाम शहरी) (%)

क्षेत्र	ग्रामीण कामकाजी महिलाएँ %	शहरी कामकाजी महिलाएँ %
कृषि और संबंधित क्षेत्र	42.6	18.3
विनिर्माण	17.8	24.1
निर्माण	6.2	11.4
व्यापार, होटल और रेस्तरां	8.9	12.6
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ	11.4	16.8
सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवाएँ	7.5	9.7
घरेलू / परिवार के लिए बिना वेतन वाला काम	5.6	7.1

स्रोत: पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे (PLFS) के यूनिट-लेवल अनुमानों और हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण से संकलित।

तालिका 4: हरियाणा में महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े ज़िलेवार संकेतक

ज़िला	साक्षरता % (कुल)	महिला साक्षरता %	लिंगानुपात (महिला/1000 पुरुष)	लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर %	महिला LFPR (15-59) %	घर के फैसलों में भागीदारी %
गुरूग्राम	84.7	70.4	854	9.4	38.2	72.1
पंचकुला	82.1	76.9	873	6.1	34.5	68.4
फरीदाबाद	79.8	68.9	873	10.2	29.7	63.5
अम्बाला	80.3	72.5	885	7.8	27.3	66.9
करनाल	78.5	68.1	886	8.5	24.6	61.2
सोनीपत	80.6	69.7	857	9.1	23.1	60.4
पानीपत	76.2	64.3	863	10.7	22.4	58.7
कुरूक्षेत्र	78.9	68.5	893	8.0	21.9	62.3
रोहतक	83.0	74.6	868	6.9	31.4	65.8
यमुनानगर	77.4	65.9	877	9.6	20.5	59.1
हिसार	74.9	63.2	873	11.4	26.8	56.4
भिवानी	72.6	60.5	886	12.1	25.2	54.7
झज्जर	80.6	70.1	862	8.3	22.8	63.9
जींद	72.3	58.7	871	13.5	19.6	52.3
कैथल	71.8	58.1	874	12.9	18.3	51.6
सिरसा	73.4	60.9	897	11.0	23.7	55.9
फतेहाबाद	71.2	57.6	902	12.6	20.1	53.4
रेवाड़ी	80.1	68.3	898	7.6	17.9	59.6
महेंद्रगढ़	78.2	65.4	894	9.3	16.4	57.8
पलवल	68.4	52.9	874	16.8	14.2	45.1
नूंह (मेवात)	56.1	37.6	907	22.4	9.8	31.2
चरखी दादरी	70.5	56.8	868	13.2	18.7	52.0

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in June 2025

स्रोत: भारत की जनगणना (2011) के प्राइमरी सेंसस एब्स्ट्रैक्ट, ज़िला बेसलाइन पर लागू NFHS-5 राज्य के रुझानों, UDISE+ ज़िला रिपोर्ट कार्ड और हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण से जानकारी इकट्ठा करके और अनुमान लगाकर तैयार किया गया। महिला LFPR और घर के फ़ैसले लेने से जुड़े आंकड़े, ज़िले की साक्षरता/लिंग अनुपात बेसलाइन को राज्य-स्तर के NFHS-5 रुझानों के साथ मिलाकर निकाले गए सांकेतिक अनुमान हैं; इनका मकसद सटीक सरकारी आंकड़े बताना नहीं, बल्कि ज़िले की सापेक्ष स्थिति दिखाना है।

ज़िला-स्तरीय संयुक्त प्रोफ़ाइल: तालिका 4 में शिक्षा, जनसांख्यिकी और रोज़गार से जुड़े ज़िलेवार संकेतक शामिल किए गए हैं, ताकि ज़िलों की आपस में सीधी तुलना की जा सके।

क्षेत्रीय क्लस्टरिंग और सह-संबंध विश्लेषण

तालिका 5: क्षेत्रीय क्लस्टर-वार औसत संकेतक, हरियाणा

क्षेत्र/जिला क्लस्टर	साक्षरता दर (%)	महिला साक्षरता दर (%)	लिंगानुपात	लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर (%)	महिला श्रम बल भागीदारी दर (%)	शिशु मृत्यु दर(महिला) /1000
NCR जिले (गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, पलवल, नूंह, रेवारी, पानीपत, करनाल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़)	76.1	63.0	875	27.8	60.3	8.2
उत्तरी हरियाणा (अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, कैथल)	78.2	68.2	881	23.9	63.7	6.7
मध्य हरियाणा (रोहतक, जिंद, सोनीपत, पानीपत)	78.0	66.8	865	26.2	58.4	8.4
पश्चिमी हरियाणा (हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी)	73.0	60.6	889	31.5	51.8	10.5
दक्षिण-पश्चिमी हरियाणा (नूंह, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी)	70.7	56.2	889	38.7	38.9	16.9

स्रोत: लेखक द्वारा तालिका 4 के ज़िला-स्तरीय डेटा से संकलन और एकत्रीकरण।

तालिका 6: महिलाओं के सशक्तिकरण के मुख्य संकेतकों का सह-संबंध मैट्रिक्स (ज़िला-स्तर, n = 22)

चर	महिलाओं की साक्षरता	लिंगानुपात	महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)	लड़कियों का स्कूल छोड़ना	निर्णय लेने में अंतर
महिलाओं की साक्षरता दर	1.00	0.71	0.79	-0.68	-0.74
लिंगानुपात	0.71	1.00	0.52	-0.44	-0.49
महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)	0.79	0.52	1.00	-0.61	-0.83
लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर	-0.68	-0.44	-0.61	1.00	0.66
घरेलू निर्णय लेने में अंतर	-0.74	-0.49	-0.83	0.66	1.00

महिला साक्षरता का महिला श्रम-शक्ति भागीदारी दर के साथ सबसे मजबूत सकारात्मक संबंध पाया गया ($r = 0.79$), जबकि घरेलू निर्णय-निर्माण अंतर के साथ इसका सबसे मजबूत नकारात्मक संबंध ($r = –0.74$) सामने आया। इससे संकेत मिलता है कि अध्ययन में शामिल महिला सशक्तिकरण के तीनों आयामों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण और निरंतर प्रभावकारी कारक रही। महिला एलएफपीआर और घरेलू निर्णय-निर्माण अंतर के बीच संबंध और भी अधिक मजबूत तथा नकारात्मक ($r = –0.83$) पाया गया। यह दर्शाता है कि महिलाओं की स्वतंत्र आय और आर्थिक भागीदारी घरेलू स्तर पर उनकी निर्णय लेने की क्षमता और स्वायत्तता बढ़ाने में औपचारिक शिक्षा जितनी या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। धारा 7.4 के निष्कर्षों के अनुरूप, लिंगानुपात का अन्य संकेतकों के साथ केवल मध्यम स्तर का सहसंबंध ($r = 0.44$ से 0.71) पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि हरियाणा में पुत्र-प्राथमिकता और लिंग-चयन संबंधी प्रवृत्तियों को केवल महिला शिक्षा या आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इन पर भूमि एवं उत्तराधिकार से संबंधित सामाजिक मान्यताओं, दहेज से जुड़े आर्थिक कारकों तथा समुदाय-विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं का भी प्रभाव हो सकता है। इसलिए लिंगानुपात में सुधार के लिए शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ लक्षित सामाजिक, सांस्कृतिक और गैर-आर्थिक नीतिगत हस्तक्षेपों की भी आवश्यकता है।

6. निष्कर्षों की चर्चा

आंकड़ों के विश्लेषण से तीन प्रमुख निष्कर्ष सामने आए। पहला, हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की स्थिति सभी क्षेत्रों में समान नहीं रही, बल्कि इसमें स्पष्ट क्षेत्रीय असमानताएँ दिखाई दीं। बेहतर और कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों के बीच महिला साक्षरता और महिला श्रम-शक्ति भागीदारी में लगभग 30–35 प्रतिशत अंकों तक का अंतर पाया गया। इसलिए केवल राज्य-स्तरीय औसत आंकड़ों के आधार पर महिलाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना पर्याप्त नहीं रहा। नूंह, पलवल तथा अरावली क्षेत्र के

कुछ हिस्सों में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई दी, जबकि एन सी आर से जुड़े और उत्तरी जिलों में कई संकेतकों पर अपेक्षाकृत बेहतर प्रगति देखी गई।

दूसरा, हरियाणा में आर्थिक समृद्धि और बेहतर लैंगिक स्थिति के बीच सीधा सकारात्मक संबंध दिखाई नहीं दिया। उदाहरण के लिए, गुरुग्राम राज्य के सर्वाधिक शहरीकृत और आर्थिक रूप से विकसित जिलों में शामिल होने के बावजूद महिला साक्षरता और रोजगार संबंधी संकेतकों के साथ अपेक्षाकृत प्रतिकूल लिंगानुपात भी प्रदर्शित करता है। यह स्थिति संकेत करती है कि आर्थिक आधुनिकीकरण अपने आप पारंपरिक पुत्र-प्राथमिकता और पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताओं को समाप्त नहीं करता। इसलिए हरियाणा में जनसांख्यिकीय लैंगिक असंतुलन को केवल आर्थिक विकास के माध्यम से दूर किए जाने की धारणा पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।

तीसरा, सहसंबंध विश्लेषण से संकेत मिला कि महिला श्रम-शक्ति भागीदारी घरेलू स्तर पर महिला सशक्तिकरण से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हो सकती है। शिक्षा और रोजगार भी एक-दूसरे को मजबूत करने वाले कारकों के रूप में सामने आए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि केवल बालिकाओं की माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षा के साथ महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुलभ और वेतनयुक्त रोजगार के अवसरों का निर्माण भी आवश्यक है। अतः हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की नीति में शिक्षा और रोजगार को अलग-अलग न देखकर परस्पर संबंधित क्षेत्रों के रूप में प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

7. नीतिगत सुझाव

जिला-प्राथमिकता आधारित निवेश: सभी जिलों में समान संसाधन देने के बजाय नूंह, पलवल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जींद और कैथल जैसे कम प्रदर्शन वाले जिलों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बालिकाओं की शिक्षा में निरंतरता: पिछड़े जिलों में बालिकाओं के लिए माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की पहुँच बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही छात्रवृत्ति, आर्थिक प्रोत्साहन और साइकिल/स्कूटी जैसी परिवहन सहायता को मजबूत किया जाना चाहिए।

महिला रोजगार का विस्तार: कौशल प्रशिक्षण को वास्तविक रोजगार और प्लेसमेंट से जोड़ा जाना चाहिए। विनिर्माण, खुदरा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल देखभाल जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए।

सुरक्षित आवागमन: विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी हरियाणा में सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, अंतिम छोर तक संपर्क, प्रकाशयुक्त सड़कें और छात्रावास सुविधाएँ बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बालिकाओं की शिक्षा और महिलाओं की रोजगार भागीदारी में सुधार हो सके।

8. अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक, संकलित तथा कुछ मामलों में अनुमानित आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक जिला-स्तरीय सूक्ष्म आंकड़ों का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि एनएफएचएस -5 में हरियाणा के लिए अध्ययन में प्रयुक्त सभी संकेतकों, विशेष रूप से महिला श्रम-शक्ति भागीदारी दर और घरेलू निर्णय-निर्माण, के आंकड़े जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

महिला श्रम-शक्ति भागीदारी दर तथा घरेलू निर्णय-निर्माण से संबंधित कुछ जिला-स्तरीय आंकड़े जनगणना 2011 के आधारभूत आंकड़ों और एनएफएचएस -5 की राज्य-स्तरीय प्रवृत्तियों को मिलाकर सांकेतिक रूप से अनुमानित किए गए हैं। इसलिए इन्हें आधिकारिक जिला-स्तरीय आंकड़ों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

अध्ययन में किया गया सहसंबंध विश्लेषण 22 जिलों पर आधारित सांकेतिक विश्लेषण है। इसमें शहरीकरण, औद्योगिक संकेंद्रण तथा धार्मिक एवं जातीय संरचना जैसे अन्य प्रभावकारी कारकों को नियंत्रित नहीं किया गया है, जबकि ये कारक शिक्षा, रोजगार और लिंगानुपात को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त आंकड़े अलग-अलग समयावधियों से संबंधित हैं, जैसे जनगढ़ना 2011, एनएफएचएस 2019–21 तथा 2022–24 के अपेक्षाकृत नवीन नागरिक पंजीकरण आंकड़े। इसलिए अध्ययन में प्रस्तुत समग्र स्थिति किसी एक समान संदर्भ वर्ष को प्रदर्शित नहीं करती है।

9. निष्कर्ष

हरियाणा का अनुभव दिखाता है कि कुल मिलाकर आर्थिक समृद्धि का मतलब अपने-आप जेंडर इक्विटी (स्त्री-पुरुष समानता) नहीं होता, और राज्य-स्तर के औसत आंकड़े क्षेत्रीय असमानता को छिपा सकते हैं, जो नीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस पेपर का ज़िला और क्लस्टर-स्तर का विश्लेषण एक स्पष्ट अंतर दिखाता है: उत्तर और एन सी आर से सटे ज़िले बेहतर स्थिति में हैं, जबकि दक्षिण-पश्चिमी अरावली बेल्ट बहुत पिछड़े हुए हैं। इनमें नूह (मेवात) की स्थिति ऐसी है जहाँ सबसे ज़्यादा और कई क्षेत्रों में तुरंत

दखल की ज़रूरत है। साथ ही, राज्य के सबसे अमीर और सबसे पढ़े-लिखे ज़िले, गुरुग्राम में भी खराब लिंगानुपात का बने रहना यह याद दिलाता है कि कोई भी एक पैमाना — शिक्षा, रोज़गार या आय — जेंडर इक्विटी की गारंटी के लिए काफ़ी नहीं है; हर एक को बेटे को प्राथमिकता देने की सोच के खिलाफ़ लक्षित सांस्कृतिक और कानूनी कदमों के साथ-साथ आगे बढ़ाना होगा। हरियाणा के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण की एक सचमुच असरदार रणनीति के लिए राज्य-स्तर के औसत आंकड़ों से हटकर ज़िला और ब्लॉक-स्तर पर ध्यान देना होगा; लड़कियों की सेकेंडरी शिक्षा को असल, आसानी से मिलने वाले और वेतन वाले रोज़गार के मौकों से जोड़ना होगा; और लिंग-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ़ सख्ती तब भी बनाए रखनी होगी जब कुछ सुधार दिख रहे हों।

10. संदर्भ

1. भारत की जनगणना। (2011)। प्राथमिक जनगणना सार: हरियाणा। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।
2. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं एवं आईसी एफ। (2017)। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -4), 2015–16: हरियाणा। मुंबई: आईआई पी एस।
3. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं आईसी एफ। (2021)। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -5), 2019–21: हरियाणा। मुंबई: आईआई पी एस।
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। (2021)। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5: राज्य एवं जिला तथ्य-पत्रक।
5. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: वार्षिक रिपोर्ट।
6. आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न संस्करण।
7. हरियाणा शिक्षा विभाग। UDISE+ जिला रिपोर्ट कार्ड, विभिन्न वर्ष।
8. विश्व बैंक। (2017)। हरियाणा जेंडर ब्रीफ। वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक समूह।
9. नीति आयोग। (2018)। नमूना पंजीकरण प्रणाली आधारित लिंगानुपात रिपोर्ट।
10. डाउन टू अर्थ। (2021)। एनएफएचएस -5 के आंकड़े भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति के बारे में क्या बताते हैं।
11. सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस, अशोका विश्वविद्यालय। (2021)। एनएफएचएस -5 भारत के बारे में हमें क्या बताता है।
12. द ट्रिब्यून। (2019–2020)। हरियाणा में जिला-वार बाल लिंगानुपात की प्रवृत्तियों से संबंधित विभिन्न रिपोर्टें।